

राजपद्ध, हिमाचल प्रदेश

(ग्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, गुक्रवार, 3 जनवरी, 1986/13 पौष, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वायत प्रशासन विभाग

ग्रधिसूचना

शिमजा-2, 5 दिसम्बर, 1985

संख्या एत0 एस0 जी 0-ए0(9)-9/९1.—हिगाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम मधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 394(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्न, हिमाचल प्रदेश तारीख 22 दिसम्बर, 1984 में इस सरकार की सम संख्यांक अधिमूचना तारीख 18 अगस्त, 1984 द्वारा प्रकाशित शिमला नगर निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 74(क) के अधीन यथाविरचित शिमला नगर निगम कर्म चारी भविष्य निधि विनियम, 1984 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियमों का अनुमोदन करते हैं:——

- 1. सक्षिप्त नाम ग्रौर प्रारम्भ.--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम शिमला नगर निगम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1985 है।
 - (2) ये विनिथम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- 2. विनियम 6 का प्रतिस्थापन.—शिमला नगर निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1984 (जिन्हें इसमें इस के पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत:
- "6. ब्याज.—जमा राशि पर ऐसी दर पर ब्याज लगेगा जैसा कि निगम द्वारा प्रति वर्ष स्रवध'रित किया जाए। वार्षिक ब्याज की गणना करते समय स्रभिदाता को देय ब्याज में पैसे निरस्त कर दिए जायेंगे फिर भी वर्ष के दौरान निर्धारित लेखों पर ब्याज, बचत बैंक लेखाओं पर प्रचलित ब्याज दर दिया जायेगा।"
- 3. विनियम 11 का संशोधन.—कथित विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के स्थीन पर निम्नलिखित उप-विनियम (1) प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः

र्वत 4-राजपत्न / 85-3-1-86--1,168.

(1)

मृत्य: 20 पैसे।

- "(1) ग्रिभिदाता को, निधि में से ग्रस्थायी ग्रिग्रिम धन की ग्रनुज्ञा, ग्रायुक्त द्वारा या किसी ग्रिधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए, निम्नलिखित शक्ति दी जा सकेगी :--
 - (क) स्रियम धन तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा,जब तक कि मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता कि स्रावेदक की धन संबंधी परिस्थितियां इसे न्यायोजित ठहराती हैं।

(ख) 48 माह के वेतन के बराबर प्रिष्मि धन, मकान या मकान के निर्माण या मकान के निर्माण या मकान के निर्माण के लिए भूमि खरीदने की लागत को चुकाने के लिए मंजूर किया जा सुक्ता: परन्तु ऐसे मामले में वसूली, 144 बराबर मासिक किस्तों में की जायेगी जैसा कि विनियम 13

के उप-विनियम (1) द्वारा अपेक्षित है;

(ग) ग्रिभिदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास ग्रपना ग्रावासिक मकान नहीं है ग्रीर उसने निधि में 5 वर्ष से कम के लिए ग्रिभिदान नहीं किया है;

(घ) ग्रिशम धन, किसी भी स्थिति में, ग्रिभिदाता के खाते में जमा ग्रिभिदान ग्रीर उस पर ब्याज से ग्रिधिक नहीं होगा;

(ङ) अग्रिम धन, एक से अधिक किस्तों में निकाला जा सकेगा।"

4. विनियम 14 का लोप.--उक्त विनियमों के विनियम 14 का लोप किया जायेगा।

5. उपाबंध "क" का लोप.--उक्त विनियमों के उपाबन्ध "क" का लोप किया जायेगा।

ग्रादेश द्वारा, हस्त/-सचिव ।